सरकार द्वारा गत तीन वर्षो के दौरान मध्य प्रदेश सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए 198.202 करोड़ रूपए दिए गए थे।

(ख) इन योजनाओं को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, उन-मिशनों और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था जिनमें 19326 स्वच्छ पेयजल सुविधा न प्राप्त और 23339 आंशिक रूप से स्वच्छ पेयजल सुविधा प्राप्त बसावटों को लाभ मिला।

(ग) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी विशेष धनराशि की मांग नही की गई हैं। तथापि, 1997-98 के लिए 8817.0 लाख रूपए के आबंटन की तुलना में 4408.05 लाख रूपए जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने भूकंप से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की योजनाओं के लिए 537.04 लाख रूपए की सहायता की मांग की हैं। केन्द्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत सहायता के रूप में 3 करोड़ रूपए की राशि जारी की हैं।

(घ) राज्यों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत परियोजनाओं/योजनाओं को अनुमोदित करने के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उप-मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जैन और मांडला जिलों के लिए दो परियोजना प्रस्ताव भेजे गए थे। इन परियोजना प्रस्तावों को क्रमशः 773.65 लाख रूपए की अनुमानित लागत से अनुमोदित कर दिया गया हैं।

बेरोजगारी/अल्प रोजगार वाले क्षेत्रों का पता लगाया जाना

2428. **श्री शमशेर सिंह सुरजेवाला** :
श्री अजीत जोगी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों में उन ग्रामीण क्षेत्रों का पता लगाया हैं जिनमें रोजगारी और अल्प रोजगार विद्यमान हैं; और

(ख) क्या सरकार इन पिछड़े राज्यों में बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू करने का विचार रखती हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : (क) और (ख) न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत विकास के लिए विशेष कार्य योजना को तैयार करने हेतु 100 सर्वाधिक पिछड़े और निर्धनतम जिलों के चयन के लिए मानदंडो की सिफारिश करने के वास्ते एक समिति गठित की गई हैं। इस समिति की पिछली बैठक 22 जुलाई, 1997 को हुई थी।

Central sponsored scheme under APMC Act, in Gujarat

2429. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:
SHRIMATl ANANDIBEN JETHABHAI PATEL:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 171 Agricultural produce Marketing Committees were set-up in Gujarat under APMC, Act, 1963 which was in operation till 31st March, 1992;

(b) whether it is a fact that the Government of Gujarat has approached the Union Government for the revival *o$* the Central Sponsored scheme under the Act;

(c) if so, the decision taken by-Government thereon; and

(d) the financial assistance proposed to be given for this purpose to the state Government during the current year and in further?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) In Gujarat. 152 principal market yards and 208 sub-market yards were in operation till 31-3-1992. Generally, each principal market yard is looked after by an APMC set up under the State Act.

(b) to (d) As per the decision of the National Develoment Council (NDC) the Centrally Sponsored Schemes for development of markets have been transferred to the State sector w.e.f. 1-4-1992.

Implementation of old *age* pension scheme

2430. SHRI J. CHITHARANJAN: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) Whether the old age pension scheme funded by Government has been implemented; and

(b) if so, the number of people in each State who got old age pension under this scheme during the year 1996-97?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) and (b) The National Old Age Pension Scheme (NOAPS) is being implemented throughout the country since 15.8.1995. During 1996-97, 4381712 persons have benefited under this scheme. A Statement showing the number of beneficiaries benefited in each State durin,? 1996-97 is given in the Statement. *(See* below).

Statement

SCHEME: NOAPS
YEAR: 1996-97

Sr. No.	States/UTs	No. of Benef.
1	Andhra Pradesh	514946
2	Arunachal Pradesh	278
3	Assam	44393
4	Bihar	652872
5	Goa	1006
6	Gujarat	102575
7	Haryana	37700
8	Himachal Pradesh	10657
9	J &K	22719
10	Karnataka	692263
11	Kerala	77169
12	Madhya Pradesh	507931
13	Maharashtra	40983
14	Manipur	1971
15	Meghalaya	4435
16	Mizoram	1204
17	Nagaland	2074
18	Orissa	280760
19	Punjab	35429
20	Rajasthan	53176
21	Sikkim	800
22	Tamilnadu	297636
23	Tripura	5987
24	Uttar Pradesh	697828
25	West Bengal	282639
26	A&N Islands	6
27	Chandigarh	NR
28	D&N Haveli	286
29	Daman & Diu	138
30	NCT Delhi	10253
31	Lakshadweep	98
32	Pondicherry	1500
	Total	4381712

NR : Not Reported